Development Council in 1982, and all these issues were considered. The National Development Council, whose members are Chief Ministers—unanimously decided that such a Council should be constituted, with nobody else than the Prime Minister of this country as Chairman of the Council and the Chief Ministers of all the States as members. The first thing that now they are doing is to draft a National Water Policy Paper to be accepted by all the concerned members.

श्री भंवर लाल पंवार : श्रीमन् मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की बैठक में राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ ? इस परियोजना के माध्यम से जोधपुर को पेय जल नवम्बर, 1985 तक उपलब्ध कराने की घोषणा की जा चुकी थी जब नवम्बर, 1983 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी जोधपुर में महा मंत्री के रूप में पधारे थे । वह जल जोधपुर को कब तक उपलब्ध करा देंगे ?

दूसरे, राजस्थान में भीषण अकाल की स्थिति है । इस वर्ष जल स्तर एक दम नीचे चला गया है, बिलकुल सूख गया है। क्या मंत्री महोदय इस समस्या का तुरन्त हल करने के लिए केन्द्र की ओर से विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ?

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, I really share the concerned of the hon. Members for his State. I know that it is a problematic State. We have been doing whatever is possible to help the State. The question that he has asked has no direct relevance to the main question.

Implementation of the National Capital Region Scheme under the Seventh Five Year Plan.

*169. SHRI RAMCHANDRA BHARADWAJ:†

SHRIMATI MAIMOONA SULTAN:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what financial provision is proposed to be made for the implementation of the National Capital Region Scheme during the Seventh Five Year Plan; and

(b) what is the extent to which the NCR projects are proposed to be implemented during the plan period?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI ABDUL GHAFOOR): (a) A provision of Rs. 35 crores has been made in the Central Sector for the NCR Schemes in the Seventh Five Year Plan.

(b) On the basis of the provision indicated in reply to part (a) of the Question, NCR projects to the extent involving Rs. 70 crores are proposed to be implemented during the 7th Plan period. According to the existing pattern the concerned States will contribute 50 per cent of the expenditure on matching basis.

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री जगप्रवेश चन्द्र ने अक्तूबर में एक वक्तव्य दिया और उसमें यह आशंका व्यक्त की कि 77 लाख की जो दिल्ली की आबादी है वह इस शताब्दी के अंत तक 140 लाख हो जायेगी और जो 20 हजार टन गारबेज अभी

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ramchandra Bharadwaj.

हम इस्तेमाल कर रहे हैं बायो फर्टीलाइजर के लिए लेकिन सचमुच गन्दगी की सफाई करने के लिए 67 हजार टन बायो फर्टीलाइजर के लिए, गारबेज हमारे पास है। मुख्य बात यह है कि यह जो परियोजना है वह इसलिए है कि दिल्ली की आबादी पर कोई और प्रेशर न पड़े और दिल्ली सुन्दर नगरी बनी रहे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में वह अभी क्या करने जा रहे हैं क्योंकि जो कार्यकारी पार्षद ने यह बयान दिया है, इसका महत्व अपनी जगह पर है लेकिन इस बयान के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?

श्री अब्दुल गफूर हम सोच रहे हैं कुछ-कुछ बातें जो जगप्रवेश चन्द्र जी ने अपने बयान में कही और जिसका जिक्र आपने किया। जो उन्होंने कहा वह भी सही है और जो आपने कहा वह भी सही है, कहीं-कहीं थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। लेकिन यह जो नेशनल केपिटल रीजन प्लान है आप जानते है कि इसी पार्लियामेंट में कब पास हुआ। यह जो बोर्ड आफ फारमेशन की बात है, डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो इसके अन्दर आते हैं, जैसे हरियाणा, राजस्थान, यू०पी०, वे लोग अपने-अपने एरिया का प्लान बना कर भेजें और सभी ने प्लान बना कर भेजा। अभी रीसेन्टली सेकिण्ड मीटिंग नेशनल केपिटल रीजन के बीर्ड की हुई जिसमें सभी लोग आए थे। डिसकशन हुआ था। जितने रुपये की जरूरत है उसके बारे में हम लोगों ने सोचा, कौन सी चीज किस हैड में दी जाए जिससे दिल्ली में जो दबाव पड़ रहा है वह कम हो। कुछ सैटेलाइट टाउन्स है राजस्थान, यू०पी० और हरियाणा के अन्दर हैं, वहां से यहां न आएं इसके लिए सेन्ट्रल सेक्टर में एक स्कीम थी रेलवेज की जिस पर करीब 90 करोड़ रुपया खर्च होगा। पानीपत से खुर्जा तक यह रेलवे लाइन थी। मकसद सिर्फ यह था कि जो सामान दूसरी जगह से यू दिल्ली आता है वह इधर से न हो वह उधर से चला जाए, प्रेशर दिल्ली पर कम रहेगा।

दूसरे टेलिकम्युनिकेशन की फेसिलिटी की बात है। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप खुर्जा चले जाइए, फरीदाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए तो कहते है कि टेलिकम्युनिकेशन नहीं है। आज कल जो मार्डन युग है इसमें टेलिकम्युनिकेशन कारोबार करने के लिए एक एसेन्शियल चीज है। और डिपार्टमेंट को कहा गया था कि इस एरिया के लिए कितना खर्च होगा। उन लोगों ने अपना इस्टीमेंट दिया है। करीब 280 करोड़ रुपये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए चाहिए। उसके बाद नेशनल हाईवेज का सवाल है। इन एरियाज में नेशनल हाईवेज को भी चौड़ा करने के लिए रुपया चाहिए। इनमें चार बाई-लैंस होनी चाहिए। इसके लिए 97 करोड़ रुपये चाहिए। यह सेन्ट्रल सेक्टर की बात है। नेशनल केपिटल रीजन के लिए 467 करोड़ रुपये चाहिए। इसके बाद स्टेट सेक्टर का सवाल भी आता है। इसमें डेवलपमेंट के लिए, इकनोमिक एक्टीविटीज के लिए भी रुपया चाहिए। फिर रीजनल रोड्स का भी सवाल है। इन इलाकों में देहातों से रोड्स लेकर नेशनल हाईवेज से जोड़ने के लिए भी रोड्स होनी चाहिए। इसके लिए 120 करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। इस तरीके से 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे ... (**व्यवधान**)।

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: He is giving a long answer. He should have laid a statement.

MR. CHAIRMAN: He wants to explain the whole of the National Capital Region scheme. what am I to do? He is asking about some garbage and he is answering...

श्री अब्दुल गफूर : जो उन्होंने पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूं। He is asking about the statement of Jag Pravesh Chandra. (*Interruptions*) श्री जगप्रवेश चन्द्र के स्टेटमेंट के बारे में पूछा है। जहां तक गारबेज हटाने का सवाल है, उनका यह सवाल पूछने का मकसद यह है कि अगर पोपुलेशन नहीं

रहेगी तो गारबेज भी कहां रहेगा । इन सब चीजों का हमने ख्याल रखा है ।

श्री रामचन्द्र भारद्वाज : मान्यवर, यह 470 करोड़ रुपयों की बात है और केवल 70 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है 70 करोड़ रुपये आप सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर देंगे । 35 करोड़ रुपये विद्यमान पद्धति के अनुसार राज्यों को देना चाहिए । जो विद्यमान पद्धति का नियम है उसके अनुसार यह राशि उनको देनी पड़ेगी । यह तो एक वेग टर्म है । ऐसी स्थिति में विद्यमान पद्धति से क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि इस राशि से कुछ काम होंगे और जो हम चाहते हैं वे हो सकेंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : इस राशि से जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमें मिली है उससे यह उम्मीद करना कि सारे प्रोबलम्स हल हो जाएंगे, यह नामुमकिन है ।

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Sir, since huge amounts are set apart in the Seventh Five-Year Plan for the NCR scheme, I want to know from the Government whether they are going to construct an ultra modern capital for the nation. This is the first part of my supplementary. Secondly, is there any proposal under the consideration of the Government to set up such regional development boards for any such city in the country?

SHRI ABDUL GHAFOOR: At present there is no such proposal.

श्री नत्था सिंह : श्रीमन, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्से और कस्बे भी इस योजना में लिए जाएंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान का भरतपुर, डींग और अलवर के इलाके भी इस योजना में आते हैं या नहीं ?

श्री अब्दुल गफूर : अलवर आता है ।

SHRI KAPIL VERMA: Sir, adjoining areas of Uttar Pradesh have been included in the NCR. I want to know what the allocations are for these regions and what schemes are being implemented.

श्री अब्दुल गफूर : आप कृपया फिर से कहिए ।

MR. CHAIRMAN: Get up and say. Don't sit and answer.

श्री कपिल वर्मा : दिल्ली की बगल में उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले है जिनके कुछ भाग नेशनल केपिटल एरजन में मिला दिये गये हैं, इस स्कीम में लाये गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन भागों के लिए, इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इन डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्सों के लिए क्या कोई स्कीम है और अगर कोई स्कीम है तो उनके लिए क्या फाइनेंशियल एलोकेशन्स हैं ?

SHRI ABDUL GHAFOOR: Broadly I have already replied about the schemes which have been discussed. And they are the railways, the telecommunications, the national highways, and then the acquisiton of lands and all these things. But the whole question rests here that due to financial constraints, we cannot move as fast as we want to.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.